www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 अंक – 302 जौनपुर मंगलवार, 23 जून 2026 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वियतनाम पहुंचे दो भारतीय युद्धपोत, नौसैनिक सहयोग को मिलेगी नई मजबूती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय नौसेना के युद्धपोत वियतनाम पहुंच चुके हैं। ये युद्धपोत नौसेना के पूर्वी बेड़े के अंतर्गत संचालित ऑपरेशनल तैनाती के हिस्से के रूप में यहां पहुंचे हैं। नौसेना के अनुसार, ष्छै उदयगिरि और ष्छै कवरत्ती 22 जून को वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी स्थित न्हा रोंग बंदरगाह पहुंचे हैं। नौसेना के युद्धपोत स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित हैं। इस नौसैनिक दल का नेतृत्व पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल आलोक आनंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस तैनाती में शामिल आईएनएस उदयगिरि एक अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट है। वहीं, आईएनएस कवरत्ती की बात करें तो यह पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता से लैस एक उन्नत कोर्वेट है। ये दोनों ही युद्धपोत भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भर नौसैनिक शक्ति का उदाहरण हैं। यहां बंदरगाह प्रवास के दौरान भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच अनेक पेशेवर गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें सैन्य विशेषज्ञों के बीच विचार–विमर्श, क्रॉस–डेक विजिट, संयुक्त खेल प्रतियोगिताएं तथा सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों देशों के वरिष्ठ नौसैनिक अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, सहयोग और साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की जानी है।

आईएमडी ने मंगलवार को मुंबई में मॉनसून के आगमन की घोषणा की

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कहा कि 23–26 जून और 29 जून को हरियाणा–चंडीगढ़–दिल्ली और पंजाब में, 23–24 जून और 29 जून को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 23 जून और 28–29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 23–29 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं–कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, दक्षिण–पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2–3 दिनों में दक्षिण–पश्चिम मॉनसून के गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों, और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैंय इसके बाद के 3–4 दिनों में झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसके आगे बढ़ने की संभावना है। इस सप्ताह पश्चिमी तट, पूर्वोत्तर भारत और उप–हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश (7–20 सेमी) होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, अगले 4–5 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अगले 2–3 दिनों में विदर्भ, दक्षिण–पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार में लू (हीट वेव) की स्थिति रहने की संभावना है।

भारत में 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल क्लास हमेशा हमारी बड़ी प्राथमिकता रहा है। इस वर्ग की 'जीवनयापन में सुगमता' के लिए सरकार ने हर स्तर पर काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में मिडिल क्लास परिवारों में एक बड़ा खर्चा डायबिटीज या ऐसी लाइफस्टाइल से जुड़े इलाज का रहता है। जन औषधि केंद्रों पर 80 परसेंट डिस्काउंट पर ऐसी दवाएं मिल रही हैं। अगर आपका पहले हजार रुपया खर्चा होता था, तो आज 200 रुपये में काम हो जाता है, 800 रुपये बच रहा है और इससे बीते वर्षों में करीब 40 हजार करोड़ रुपए की बचत देश के अनेक परिवारों की हुई है। उन्होंने कहा, "मिडिल क्लास के बजट का एक बड़ा हिस्सा बुजुर्गों के इलाज पर भी जाता है। आज 70 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।" सोमवार को नई दिल्ली में एक निजी समाचार चौनल के समिट में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2014 के बाद, हालात को बदलने के लिए हम राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़े, हम निकल पड़े। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 12 साल, मिडिल क्लास के लिए कमाई के साथ–साथ बचत के भी रहे हैं। 2013–14 में, लगभग 2 लाख रुपए तक की आय होने पर टैक्स लगता था, आप सबको वो नसीब रहा होगा। और यह टैक्स मिडिल क्लास देता रहता था। आज 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। यानी टैक्स फ्री इनकम कई गुणा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, "ळैज रिफॉर्म्स के कारण भी मिडिल क्लास को बहुत सुविधा हुई है। टैक्स फाइलिंग का समय और खर्चा भी बच गया है। क्योंकि यह बहुत ही आसान हो गया है। घर बैठे ही प्ज्त फाइल हो रहे हैं, अगर कोई सेटलमेंट का इश्यू है, तो वो फेसलेस हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि साढ़े 9 हजार से अधिक मोबाइल टावर बनाए गए हैं। करीब 45,000 गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई। नक्सल प्रभावित जिलों में 1800 से अधिक बैंक ब्रांच खोली गई।

राष्ट्रपति मुर्मु आज 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज मंगलवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले 'सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी–2' में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार पाने वाले 65 लोगों में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन, टेनिस स्टार विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। शाम 5 बजे शुरू होने वाले समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल होंगे। दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति 65 पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी, जिनमें दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और 56 पद्म श्री शामिल हैं। राष्ट्रपति ने 25 मई को आयोजित पहले नागरिक सम्मान समारोह में 65 पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे, जिनमें दो पद्म विभूषण, छह पद्म भूषण और 57 पद्म श्री शामिल थे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये पुरस्कार कला, समाज सेवा, जन–कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे अलग–अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 'पद्म विभूषण' असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, 'पद्म भूषण' उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए और 'पद्म श्री' किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण के लिए चुना गया है।

कतर हादसे में 12 भारतीयों की मौत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया गहरा शोक

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए दर्दनाक हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने घटना की पुष्टि करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने घटना पर शोक जताया और पीड़ित परिवार के प्रति दुख जाहिर किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कतर के रास लफ्फान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए धमाके में भारतीय नागरिकों समेत कई लोगों की मौत और घायल होने से बहुत दुख हुआ। जैसे–जैसे और जानकारी सामने आ रही है, हमारा दूतावास कतर के अधिकारियों के संपर्क में है और इस हादसे से प्रभावित भारतीय नागरिकों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रही है। हमारी प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।" कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने एक्ष्स पोस्ष्ट में पुष्टि करते हुए बताया, "रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। हम इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने सोशल मीडघ्यिा प्ष्लेटफॉर्म 'एक्ष्स' पोस्ष्ट में पुष्टि करते हुए बताया, "रविवार रात हुए रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है।

बिचौलियों की भूमिका होगी कम, किसानों को मिलेगा पूरा फायदा : अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड) के ऑक्शन पोर्टल एनएएफईएक्स डॉट इन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'नाफेड' ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण के रूप में चार पहलों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि जो नाफेड 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, वह आज 500 करोड़ मुनाफे और 30 हजार करोड़ टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सहायता कर रहा है। 2014 में नाफेड गहरे आर्थिक संकट मे था। नाफेड के अधिकारियों ने पीएम मोदी के साथ बैठक की। इसके बाद भारत सरकार ने आर्थिक मदद करके नाफेड को फिर से मजबूती के साथ चालू किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मुझे पता है कि नाफेड गहरे आर्थिक संकट में था। आने वाले दो वर्षों में सहकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा दलहन का एक दाना भी व्यापारियों के माध्यम से न आए बल्कि सीधे किसानों के पास से आए। इससे किसानों को सीधा मुनाफा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही दलहन का दाम किसानों तक पहुंचेगा, अपने आप दलहन का रकबा बढ़ने लगेगा और देश एक प्रकार से दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से सीधे खरीद के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है। मेरा मानना है कि नाफेड की ओर से भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करना होगा, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे। अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मेरे जैसे कई भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए 23 जून का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक विधान, एक निशान और एक प्रधान के सूत्र को चरितार्थ और देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के बड़े नेता रहे हैं। उन्होंने प्रसिद्धि के लिए कुछ नहीं किया और उन्होंने जो कुछ किया, उसके दूरगामी परिणाम रहे।

यमुना जल बंटवारे पर तीन दशक पुराना गतिरोध खत्म

हरियाणा, (एजेंसी)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में पानी के विभिन्न मुद्दों पर बैठक की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि आज की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दोनों मौजूद थे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने 1994 में हुए समझौते के तहत हरियाणा के अतिरिक्त पानी के मुद्दे पर चर्चा की। आज इस बात पर सहमति बनी कि एक नया समझौता किया जाएगा ताकि यह पक्का किया जा सके कि राजस्थान को उतना पानी मिले जितना उसे मूल रूप से समझौते के तहत आवंटित किया गया था। पानी को पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा और दोनों राज्य इस व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। उम्मीद है कि अगले सोमवार तक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसका आदान–प्रदान होगा। आज इस फैसले को अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम सैनी ने बताया कि बैठक में हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य जल वितरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा हुई। हमारा प्रयास है कि संवाद और सहयोग की भावना के साथ जल संसाधनों के न्यायसंगत एवं प्रभावी प्रबंधन की दिशा में सार्थक समाधान सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के प्रयासों से लगातार बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों का मकसद जल प्रबंधन और यह सुनिश्चित करना है कि पानी हर व्यक्ति तक पहुंचे। लखवार, किशाऊ और रेणुका बांध परियोजनाओं पर सहमति बन गई है। इसके परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं से पानी उपलब्ध होगा और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस पानी को राजस्थान तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। हाल की चर्चाओं में इस बात पर भी सहमति बनी कि मानसून के दौरान बेकार बह जाने वाले बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए।

लखनऊ अग्निकांड– चार अधिकारी निलंबित, बिल्डिंग मालिक फरार

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। हादसे के बाद प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू कर दी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। निलंबित किए गए अधिकारियों में गौरव कुमार, एक्सईएन कलेक्शन जानकीपुरम, कमलेन्द्र कुमार सिंह, एफएसएसओ इंदिरा नगर, अनिल कुमार, सहायक अभियंता (एई) और प्रमोद पांडे, जूनियर इंजीनियर (जेई) शामिल हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इन अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई। अलीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार को हुई आगजनी के संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, थाना अलीगंज में अपराध संख्या 115/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 105, 125, 3(5) और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा 6'10 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मुकदमा छह नामजद अभियुक्तों और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, 4 गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 23 जून को घोषणा की कि लखनऊ के अलीगंज इलाके में लगी जानलेवा आग, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सखत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। पाठक ने कहा कि कल रात से अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में सखघ्त कार्रवाई की जाएगीय किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस सांसद जेबी माथर ने ऐसी घटनाओं के बार–बार होने पर चिंता जताई और जवाबदेही तय करने और सुरक्षा के बेहतर नियम लागू करने की मांग की। उन्होंने ।छप् से कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाएं बार–बार होती रहती हैं – हमने इसे दिल्ली में देखा और अब लखनऊ में। ऐसी घटनाओं पर नजर रखने के लिए क्या सिस्टम है? सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि क्या गड़बड़ हुई और यह पक्का करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं कहीं भी दोबारा न हों। लखनऊ पुलिस ने अलीगंज पुलिस स्टेशन इलाके की उस बिल्डिंग को सील कर दिया है जहां आग लगी थी। आम लोगों के आने–जाने पर रोक लगा दी गई है क्योंकि फोरेंसिक और फायर डिपार्टमेंट की टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं। जगह को सुरक्षित रखने और जांच में मदद के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

तनाव और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही दुनिया में ब्रिक्स की है खास भूमिका – अजित डोभाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स केवल देशों के समूह से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इसे दुनिया की लगभग आधी आबादी का एक सामूहिक घर बताया, जिसकी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में "खास भूमिका" है। खासतौर से ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बढ़ती अस्थिरता, भू–राजनीतिक तनाव और बदलते सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सालहकारों की मीटिंग में एनएसए अजित डोभाल ने अपने समकक्षों का स्वागत किया और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने समूह के अंदर सहयोग को आगे बढ़ाने में लगातार जुड़े रहने और समर्थन के लिए हिस्सा लेने वाले देशों को धन्यवाद दिया। एनएसए अजित डोभाल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "मैं आज आपकी मौजूदगी और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के आपके लगातार कमिटमेंट के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।" मौजूदा वैश्विक हालात को हाइलाइट करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया एक खास तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसमें हथियारों से जुड़ी लड़ाइयां, भू–राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक दबाव और ऐसी विघटनकारी प्रौद्योगिकी का आना शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को बदल रही हैं। उन्होंने कहा, "हम बहुत मुश्किल समय में मिल रहे हैं। दुनिया सैन्य झगड़ों और मुश्किल सुरक्षा समस्याओं से जूझ रही है। यह भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक दबाव और विघटनकारी प्रौद्योगिकी का सामना कर रही है।" एनएसए अजित डोभाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने जो चुनौतियां हैं, वे तेजी से मुश्किल होती जा रही हैं और उन्हें मैनेज करना कठिन हो रहा है, जबकि मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क और झगड़े सुलझाने के तरीके असरदार तरीके से जवाब देने में मुश्किल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "न केवल खतरे और अधिक जटिल तथा आपस में जुड़े हुए होते जा रहे हैं, बल्कि उनसे निपटने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए मौजूद साधन और संस्थागत तंत्र भी लगातार अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।" बहुपक्षीय सहयोग के कमजोर होने पर चिंता जताते हुए, एनएसए डोभाल ने कहा कि ग्लोबल सिस्टम में बहुपक्षवाद में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे समय में जब मिलकर काम करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने ब्रिक्स बनाने के पीछे के असली विजन को याद करते हुए कहा, "बहुपक्षावाद कम हो रहा है।" एनएसए अजित डोभाल के अनुसार, ब्रिक्स को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक अनौपचारिक समूह के तौर पर सोचा गया था, जिसका मकसद ज्यादा "मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर" को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना था।

संपादकीय

स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित

2024 में देश में कुल जितनी मौतें हुईं, उनमें से 45.5 प्रतिशत लोग बिना किसी इलाज के काल–कवलित हुए। गांवों में ये आंकड़ा 48.9 फीसदी रहा। ये आंकड़े बदतर होते हालात की झलक देते हैं। चौंकाने वाला यह आंकड़ा संकेत है कि किस तरह आम लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित होते जा रहे हैं। इसके मुताबिक 2024 में देश में कुल जितनी मौतें हुईं, उनमें से 45.5 प्रतिशत लोग बिना किसी इलाज के काल– कवलित हुए। गांवों में ये आंकड़ा 48.9 फीसदी रहा। सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) सांख्यिकी रिपोर्ट में शामिल ये आंकड़े बदतर होते हालात की झलक देते हैं। गौरतलब है कि 2020 में इलाज से वंचित रहते हुए मरे लोगों की संख्या 18 प्रतिशत थी। एसआरएस रिपोर्ट में उन व्यक्तियों की मौत को बिना इलाज की श्रेणी में रखा जाता है, जो मृत्यु के समय प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी की देखभाल में नहीं थे। ऐसी मौतों की संख्या में तेज वृद्धि को लेकर विशेषज्ञ भी भौंचक हैं। उनके मुताबिक कारण स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, इलाज का महंगा हो जाना या फिर आंकड़ा जुटाने की विसगंतियां हो सकती हैं। मगर विसंगतियों की बात एक दूसरे आंकड़े से कमजोर नजर आने लगती है। इसके मुताबिक 2024 में कुल मौतों के बीच सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पतालों में हुई मौत का जो अनुपात रहा, वह 2014 की संख्या के आसपास ही है। मतलब यह कि इस दौर में अस्पताल सेवाओं का ऐसा विस्तार नहीं हुआ, जो आम जन को सुलभ हो। अब जरूरत इस बात की है कि एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट से मिले संकेतों की अधिक गहराई से पड़ताल की जाए। मगर मौजूदा सरकार का जो नजरिया है, उसके बीच ऐसा होने की उम्मीद कम ही है। संभवतरू अप्रिय तथ्यों से बचने के प्रयास का ही यह उदाहरण है कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस)–6 की जारी रिपोर्ट में रक्तक्षीणता (एनिमिया), पांच वर्ष से कम उम्र में होने वाली मौतों, शौचालय और स्वच्छ रसोई गैस की उपलब्धता आदि से संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं। एनएफएचएस–5 से सामने आया था कि 15–49 वर्ष उम्र वर्ग में 57 फीसदी महिलाएं एनिमिया ग्रस्त हैं। ये स्थितियां स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आम पालन–पोषण बढ़ी गैर–बराबरी और बड़ी संख्या लोगों के वंचित होते जाने का संकेत हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये हकीकतें आम बहस से दूर बनी रहती हैं।

अगर धमकी देते देते पाकिस्तान ने सचमुच युद्ध छेड़ दिया तो भारत करेगा

नीरज

बड़बोले ख्वाजा आसिफ कभी भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं, कभी जल युद्ध की हुंकार भरते हैं और कभी देशी विदेशी मीडिया को दिए गए साक्षात्कारों में यह कबूल करते नजर आते हैं कि हर जंग में पाकिस्तान की फौज को भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ताजा गीदड़ भभकी भी उसी बौखलाहट का नतीजा है, जो आतंकवाद के सहारे भारत को अस्थिर करने की नाकाम कोशिशों के बाद अब पानी के मुद्दे पर नया शोर मचा रही है। असलियत यह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों ही अपने ही देश की नाकामियों को छिपाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध की गीदड़भभकी दी है। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान की जल सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ तो इस्लामाबाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने पानी को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बताते हुए आरोप लगाया कि भारत अगर जल आपूर्ति रोकने की दिशा में आगे बढ़ता है तो हालात युद्ध तक पहुंच सकते हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि ा को निलंबित कर पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया था कि आतंकवाद और बातचीत अब साथ–साथ नहीं चल सकते। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई सिंधु जल संधि के तहत सिंधु बेसिन से मिलने वाले जल से पाकिस्तान की करीब अस्सी प्रतिशत खेती चलती है। लेकिन दशकों तक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को अब इस बात का डर सताने लगा है कि संधि स्थगित होने के बाद भारत अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत अपने अधिकार के पानी का इस्तेमाल बढ़ाएगा, वैसे वैसे पाकिस्तान की पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था पर संकट और गहराता जाएगा। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने भारत पर चिनाब नदी के प्रवाह को हथियार की तरह इस्तेमाल करने और जल संबंधी सूचनाएं रोकने का आरोप लगाया है। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान इस समय गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। सिंध के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कई नहरों में भारी जल कमी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब प्रांत पर तय हिस्से से ज्यादा पानी लेने के आरोप लग रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के प्रांतों के बीच पानी को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी अपने ही घर में जल संकट और अव्यवस्था संभालने में नाकाम पाकिस्तान अब भारत पर आरोप लगाकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि यह पुराना भारत नहीं है। पिछले महीने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया था कि भारत हर चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और यदि जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तीनों सेनाएं चौबीसों घंटे तैयारी कर रही हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल मजबूत किया जा रहा है और भविष्य के युद्ध की हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। जनरल द्विवेदी का यह बयान भारत की सैन्य शक्ति और आत्मविश्वास का परिचायक था। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध का मैदान पूरी तरह पारदर्शी हो चुका है, जहां दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। भारतीय सेना सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर सजग है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि भारत अब हर मोर्चे पर निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखता है। आतंकवाद, घुसपैठ, जल विवाद या सीमा पर उकसावे की हर हरकत का जवाब नए भारत की सेना उसी भाषा में देना जानती है।

ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की कमजोरी और डर को उजागर करती हैं, जबकि भारतीय सेना का शौर्य, अनुशासन और तैयारी यह साबित करती है कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को इस बार बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फिर भी यदि मान लिया जाए कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिमाकत करता है तो सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा? इसका जवाब यह है कि इस बार भारत की ओर से केवल सीमा पर जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को ऐसी मार झेलनी पड़ सकती है जिसकी कल्पना भी इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने नहीं की होगी। भारतीय सेनाध्यक्ष के बयानों के अलावा, दुनिया भर की रक्षा रिपोर्टों और सैन्य विश्लेषणों का अध्ययन बताता है कि पारंपरिक युद्ध क्षमता, आधुनिक हथियारों, आर्थिक ताकत, सैन्य तकनीक और रणनीतिक तैयारी के मामले में भारत पाकिस्तान पर कई गुना भारी पड़ता है। हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे अनुभवी और विशाल सेनाओं में शामिल भारतीय थलसेना के पास सैनिक संख्या, आधुनिक तोपखाना, मिसाइल शक्ति और युद्धक टैंकों का ऐसा जाल है जो पाकिस्तान की जमीनी रक्षा को चंद दिनों में चरमरा सकता है। भारत के पास पिनाका बहु नली रॉकेट प्रणाली, धनुष तोप, ज्ञ90 अजय टैंक,

ज्90 भीष्म टैंक और ब्रह्मोस जैसी घातक मारक क्षमता है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से कई गुना तेज रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है। हाल के वर्षों में भारत ने स्वदेशी रक्षा निर्माण को तेजी से मजबूत किया है, जिसके कारण सेना को लगातार आधुनिक हथियार और तकनीक मिल रही है। भारतीय सेना का सबसे बड़ा फायदा उसका वास्तविक युद्ध अनुभव और ऊंचे पर्वतीय इलाकों से लेकर रेगिस्तान तक हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता है। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना लंबे समय से आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सीमित संसाधनों से जूझ रही है। साथ ही भारत की रक्षा बजट क्षमता पाकिस्तान से कई गुना अधिक है, जिससे हथियारों की खरीद, तकनीकी उन्नयन और युद्ध तैयारी लगातार मजबूत होती जा रही है। साथ ही भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर है जबकि पाकिस्तान पूरी तरह चीन और दूसरे देशों पर निर्भर है। वहीं भारतीय वायुसेना की बात करें तो यह वह ताकत है जो किसी भी आधुनिक युद्ध का रुख घंटों में बदल सकती है। भारतीय वायुसेना के पास रॉफेल, सुखोई तीस एमकेआई, तेजस और मिराज जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हैं। रॉफेल को दुनिया के सबसे खतरनाक बहुउद्देशीय युद्धक विमानों में गिना जाता है। इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और अत्याधुनिक राडार प्रणाली पाकिस्तान के अधिकतर विमानों पर भारी पड़ सकती है। कई वैश्विक सैन्य अध्ययनों में माना गया है कि भारत की वायु शक्ति संख्या और तकनीक दोनों में पाकिस्तान से बहुत आगे है। भारतीय वायुसेना की सबसे घातक ढाल एस–400 वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती है।

भारत में रोजगार का सवाल अब स्थिरता पर क्यों निर्भर है

डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन

जब 1954 में सर आर्थर लुईस ने गरीब अर्थव्यवस्थाओं के अमीर बनने की परिघटना को समझाने का काम शुरू किया, तो उन्होंने विकास की मुख्य प्रक्रिया को पूंजी के संचय के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के जीवन–निर्वाह वाली खेती से हटकर अधिक कमाई वाले उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों की ओर मुड़ने के तौर पर पहचाना। उनका यह अनुमान बिल्कुल ही सही था कि यही बदलाव देर से औद्योगीकरण करने वाले हर देश का भविष्य तय करेगा। आज भारत ठीक इसी मोड़ पर खड़ा है और नीति–निर्माताओं के सामने सवाल पर्याप्त नौकरियां उपलब्ध कराने भर का नहीं है। बल्कि, उनके सामने इससे भी अधिक अहम सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी नौकरियां पैदा करने की स्थिति में है या नहीं जो पर्याप्त तादाद में हों, औपचारिक हों और एक युवा कामगार को जीवन भर बढ़ती उत्पादकता एवं सुरक्षा दे सकने लायक टिकाऊ हों। इस जिम्मेदारी के भार को काफी सटीकता से बताया जा सकता है। श्आर्थिक समीक्षा 2023–24श ने श्रावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे)श और आबादी से जुड़े अनुमानों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि इस दशक की बाकी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था को हर वर्ष लगभग 78.5 लाख गैर–कृषि नौकरियां सृजित करनी होंगी। यह आंकड़ा दो बढ़ते दबावों का नतीजा है। पहला, कामकाज के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ने के साथ श्रमशक्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरीय और दूसरा, संरचनात्मक बदलाव के कारण खेती से बाहर आने वाले कामगार। रोजगार में खेती की हिस्सेदारी अभी भी लगभग 46 प्रतिशत है। वर्ष 2047 तक इस हिस्सेदारी के घटकर एक–चौथाई तक आ जाने की संभावना है। जुलाई 2025 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई और उसके अगले महीने से शुरू हुई श्प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनाश् उस अंतर को पाटने की अब तक की सबसे सोची–समझी कोशिश है। इस योजना के तहत, जुलाई 2027 तक की दो वर्षों की अवधि में 3.5 करोड़ से अधिक औपचारिक नौकरियां सृजित करने हेतु श्कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)श के जरिए 99,446 करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। ईपीएफओ में पंजीकृत किसी कंपनी में पहली बार शामिल होने वाला और महीने में एक लाख रुपये से कम कमाने वाला कामगार, दो किस्तों में कुल 15,000 रुपये तक पाने का हकदार बन जाता है। दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम (फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स) करने पर और बचत (सेविंग्स) के तौर पर मिलती है। वहीं, निर्धारित आधार–रेखा (बेसलाइन) से अधिक लोगों को नौकरी पर रखने वाले नियोक्ताओं को हर नए कामगार के लिए महीने में 3,000 रुपये तक मिलते हैं। ये शर्तें कुछ इस तरह तय की गई हैं कि छोटी कंपनियां भी इसके दायरे से बाहर हो जाने के बजाय इसमें शामिल हो सकें। यह योजना भर्ती संबंधी सब्सिडी वाले आम व निराशाजनक तरीकों से इसलिए अलग और बेहतर है क्योंकि इसमें पहला लाभ मिलने से पहले छह महीने तक लगातार नौकरी करना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार काम करने वाले को नौकरी पर रखने का लाभ तभी मिलता है जब वह कर्मचारी काम में कुशल बन जाए और टिका रहे। यह शर्त शुरुआती भर्ती को एक पक्की प्रतिबद्धता में बदल देती है, जिससे नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत वसूलने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है और कर्मचारी को भी उतने महीने मिल जाते हैं जिनमें वह असली हुनर सीख सके और भरोसेमंद रिकॉर्ड बना सके। इस तरह, यह योजना केवल नौकरी देने के लिए नहीं बल्कि कर्मचारी को बनाए रखने की अपेक्षाकृत अधिक कठिन प्रक्रिया के लिए पुरस्कृत करती है और इसके बाद कर्मचारी के पास रोजगार क्षमता एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होता है जिसका वह कहीं भी सदुपयोग कर सकता है। इस योजना का सबसे अधिक झुकाव मैन्युफैक्चरिंग की ओर है, जहां नियोक्ता को मिलने वाला प्रोत्साहन दो वर्ष के बजाय चार वर्ष तक मिलता है। समय–सीमा को दोगुनी करने का यह निर्णय औद्योगिक क्षमता तैयार होने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखकर लिया गया है। इसी तरह, इससे निर्माता (मैन्युफैक्चरर) समय से पहले स्वचालित व्यवस्था (ऑटोमेशन) लाकर कामगारों को हटाने के बजाय श्रमशक्ति बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं। अहम बात यह है कि सरकार ने इसे देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से जरूरी माना है। ईपीएफओ के जरिए, हर नए कामगार को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का पहला बार अहसास होता है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत कम कामगारों को यह सुरक्षा मिल पाती है। इस योजना के शुरुआती नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं।

अपने घरों की ओर भी लौटें घरेलू पर्यटक

कमल

उदारीकरण के पहले तक गर्मी की छुट्टियों का मतलब, जरूरी सेवाओं को छोड़ सबकी छुट्टियां होती थीं, स्कूल बंद हो जाते थे, अदालतों में जरूरी फौजदारी मामलों को छोड़ सुनवाई रूक जाती थी, और अदालतें बंद हो जाती थीं, तहसीलों में भी सूनापन छा जाता था, बैंकों में भी आधे से ज्यादा लोग गर्मी की छुट्टियां ले लेते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सूचना और संचार क्रांति के कारण पहले की तुलना में बिजली ज्यादा मिलने के चलते अब शहरों को कौन कहें, गांव तक पूरी रात गुलजार हो रहे हैं। इसका असर छुट्टियां मनाने के अंदाज और छुट्टियों के लिए जगह के चयन पर भी पड़ रहा है। पहले छुट्टियों का मतलब होता था, नौकरीपेशा लोगों की गांवों में वापसी। गांव में रहने वाले बच्चे छुट्टियों में नानी, मामा, मौसी के घर जाते थे। बहुत हुआ तो कोई तीर्थ यात्रा कर ली गई या शहर में रह रहे रिश्तेदार के यहां यात्रा कर ली गई। अब छुट्टियों का मतलब साफ तौर पर बदल गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी, ज्यादातर गांव खाली हो चुके हैं। गांवों में वे ही लोग रह रहे हैं, जिनके पास जायदाद ज्यादा है या जिनकी हैसियत नहीं है कि शहर जा सकें। उत्तर भारत के गांवों का दौरा करेंगे तो पाएंगे कि हर तीसरे घर में या तो ताला लगा है कि उस घर के पांच सदस्यों में से तीन किसी शहर में हैं। शहर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी या बगल का कस्बा भी। जिसको जहां नौकरी मिली, कम से कम उसका परिवार वहीं रह रहा है। सरकारी तंत्र की शिक्षा पर विशेषकर राज्यों की ओर से खूब खर्च हो रहा है। अध्यापक भी तैनात हैं। कागजों में ग्रामीण स्कूलों को सहूलियतें भी खूब दी जा रही हैं, लेकिन गांवों के स्कूलों में उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी माली हालत छोटे स्कूल का खर्च उठाने लायक नहीं है। अन्यथा सभी अपनी हैसियत के मुताबिक महानगर, शहर या बगल के कस्बे के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्ड पर ग्रामीण जनसंख्या अब भी करीब दो तिहाई से ज्यादा है। लेकिन हकीकत में इसकी संख्या बेहद कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 68.8 आठ फीसद जनसंख्या गांवों में रहती थी। लेकिन भारत सरकार के हालिया अनुमानों के मुताबिक, करीब 63 प्रतिशत जनसंख्या ही गांवों में रह रही है। लेकिन यहां एक बार फिर ध्यान देने की है कि इसका भी बड़ा हिस्सा शहरों में रह रहा है। भले ही शहर में उसकी रिहायश किसी झुग्गी या किसी झुग्गीनुमा शहरीकृत गांव में हो। औद्योगिक इलाकों में रहने वाले लोगों की रिहायशी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसकी तुलना में उनका ग्रामीण घर बढ़िया है। फिर भी रोजगार और शिक्षा के लिए कम कमाई के बावजूद ग्रामीण परिवार शहरों में रहने को मजबूर हैं। यह चर्चा लंबी हो सकती है। आज छुट्टियों में हर परिवार अपनी हैसियत के हिसाब से घूमने जा रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादातर घूमने के लिए पहले की तरह अपने गांवों की ओर नहीं लौट रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारत के घरेलू पर्यटन में साल 2023–24 की तुलना में 2024–25 में करीब 95 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दिख रही है। इस साल 250 करोड़ से ज्यादा लोगों ने घरेलू पर्यटन किया। इन पर्यटकों का पूरा विवरण यानी किस इलाके के कितने पर्यटक किस इलाके में घूमने गए। लेकिन मोटे तौर पर सबसे ज्यादा नए तीर्थस्थलों मसलन काशी के विश्वनाथ कारीडोर, उज्जैन के महाकाल कारीडोर या केदारनाथ आदि की यात्राएं की। लेकिन गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी आता है कि पहाड़ों में लोगों को ठहरने के लिए जगह तक नहीं मिलती, लोग कारों में सड़कों के किनारे ही रहने और अपनी दैनिक क्रिया करने को मजबूर हो जाते हैं। स्पष्ट है कि ये पर्यटक इन जगहों पर जाकर वहां खर्च भी कर रहे हैं। इसका आर्थिक फायदा उन्हीं इलाकों को मिल रहा है। यहीं पर एक सवाल उठता है कि अगर इन पर्यटकों में से एक हिस्सा अपने गांवों की यात्रा करेगा तो वह जो खर्च करेगा, उस खर्च से उसके गांव–परिवार के आसपास की आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसका असर यह होगा कि उन इलाकों में आर्थिक विकास बढ़ेगा। आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से उन इलाकों की सूरत भी सुधरेगी। भारतीय परंपरा में व्यक्ति के विकास के लिए पूरे परिवेश के योगदान को स्वीकार किया जाता रहा है। इसीलिए व्यक्ति की कमाई और उपलब्धि में उसके परिवेश और परिवार का हिस्सा माना जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शतक वर्ष में पंच परिवर्तन की जो सैद्धांतिकी और कार्ययोजना स्वीकार की है, उसका दूसरा अंग कुटुंब प्रबोधन है। संघ के पंच परिवर्तन में भारतीय संस्कृति की उस अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जिसमें परिवार सिर्फ सामाजिक संस्था नहीं माना जाता, बल्कि संस्कार की प्रयोगशाला के रूप में स्वीकार्य है। आर्थिक उदारीकरण के बाद जीवन में यांत्रिकता बढ़ी है। इसकी वजह से आपसी संवाद भी घटा है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा तो खैर मिला है, इससे परिवार टूट रहे हैं। ऐसे में कुटुंब यानी परिवार प्रबोधन की आवश्यकता पहले से अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए संघ ने अपने श्परिवार प्रबोधन अभियानश् के तहत देशभर में मिलकर भोजन करने, साप्ताहिक पारिवारिक संवाद की परंपरा को बढ़ावा देने, पारिवारिक सांस्कृतिक आयोजन करने जैसी कोशिशें तेज कर दी हैं। घरेलू पर्यटन के तहत अगर लोगों को छुट्टियों में उनके ही गांवों में कुछ दिन गुजारने के लिए अगर प्रेरित किया जाए तो यह कुटुंब प्रबोधन का विस्तार होगा। अगर घरेलू पर्यटन को पर्यटकों को उनके मूल गांवों, ढाणियों और कस्बों की ओर मोड़ा जाएगा तो उनके साथ उनके बच्चे भी अपने गांवों जाएंगे, इससे शहरों में रह रहे बच्चे का अपनी मूल भूमि और कुटुंब से जुड़ाव बढ़ेगा। फिर हो सकता है कि भविष्य में वे अपने गांवों से ज्यादा गहरा जुड़ाव महसूस करेंगे। इससे सामाजिक संबंधों पर जहां सकारात्मक असर पड़ेगा, वहीं लोगों को अपनी माटी, अपने परिवार और अपने समाज से रिश्ता और गहरा होगा। चूंकि वे अपने गांव नियमित अंतराल पर लौटते रहेंगे, छुट्टियों का हिस्सा अपने गांवों में गुजारेंगे तो उनके जरिए उनके अपनी माटी और इलाके में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। पड़ोसी देश चीन ने आर्थिक मंदी के दौर में घरेलू खर्च और स्ट्रीट कारोबार को बढ़ावा देने की नीति पर काम किया। इससे घरेलू पर्यटन को वहां बढ़ावा मिला, घरेलू स्तर पर खर्च भी बढ़ा, इसका अच्छा प्रभाव चीन की घरेलू आर्थिकी पर पड़ा। अब तो बसंत के मौसम में चीन की सरकार लोगों को अपने गांवों की यात्रा करने के लिए लंबी छुट्टियां देती है। उस दौरान लोग अपने मूल निवास, गांव, कस्बे आदि की यात्रा करते हैं।

एफटीए विकसित भारत के लिए नई व्यापार संरचना का निर्माण कर रहे हैं

राजेश अग्रवाल

विकसित भारत का विजन हासिल करने के लिए अगले दो दशकों तक आर्थिक विकास की उच्च दर बनाए रखना जरूरी है। भारत का विशाल घरेलू बाजार इस विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इंजन है, लेकिन केवल इसी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धी पैमाने और वास्तविक तकनीकी परिवर्तन हासिल करने के लिए, भारत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के नेटवर्क के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ मजबूती से एकीकृत हो रहा है। जहां डब्ल्यूटीओ समझौते नियम–आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए आधारशिला प्रदान करते हैं, वहीं एफटीए इच्छुक साझेदारों को डब्ल्यूटीओ आधारशिला पर आगे बढ़ाते हुए रुचि के अन्य क्षेत्रों में अधिक गहराई से एकीकरण करने में सक्षम बनाते हैं। आर्थिक एकीकरण और साझेदार देशों के अनुसार नियम बनाने के महत्वपूर्ण चालक के रूप में वर्तमान में लागू 384 अधिसूचित एफटीए अपनी उपयोगिता रेखांकित करते हैं। ये एफटीए महत्वपूर्ण बाजार तक पहुंच बनाने और भारतीय व्यवसायों को वैश्विक भू–राजनीतिक उथल–पुथल के अनिश्चित हालात से बचाने के लिए संस्थागत रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) हैं। वैश्विक आर्थिक अवसरों तक पहुंच भी उन भारतीय व्यवसायों के लिए जरूरी है, जो बड़े पैमाने पर काम करके वैश्विक चैम्पियन के तौर पर उभरना चाहते हैं। लेकिन फायदा केवल बड़े व्यवसायों तक सीमित नहीं है। एफटीए स्टार्ट–अप, एमएसएमई, किसानों, मछुआरों और भारतीय प्रतिभा के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर के द्वार खोलते हैं, जो अपनी क्षमताओं का विश्व स्तर पर लाभ उठाना चाहते हैं। ये बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ टैरिफ, सेवा बाजार तक पहुंच और पारदर्शी व्यापार नियमों को शामिल करती हैं, जिससे भारतीय व्यवसायों को लंबी अवधि के निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण मिलता है। भारत की व्यापार बातचीत की रणनीति काफी विकसित हो चुकी है, और इसका ध्यान उन पूरक अर्थव्यवस्थाओं पर है, जो वस्तु और सेवाओं के लिए मुख्य निर्यात बाजार के रूप में काम करती हैं। हाल के मुक्त व्यापार समझौतों का एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में समान अवसर प्राप्त हों। यह समानता विशेष रूप से वस्त्र, परिधान और जूते जैसे श्रम–गहन क्षेत्रों के लिए जरूरी है, जहां ऐतिहासिक रूप से भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगता रहा है, जबकि प्रतिस्पर्धियों को शुल्क मुक्त पहुँच मिलती है। कनाडा, इजराइल और ईएईयू और एमईआरसीओएसयूआर जैसे समूहों के साथ भी भारत व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। सेवाएं भारत की निर्यात रणनीति और इसके एफटीए वार्ताओं के केंद्र में हैं। सीमापार डिजिटल डिलीवरी पर पक्के वादे करके, हाल के एफटीए, तेजी से बढ़ते वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) इकोसिस्टम, तकनीकी स्टार्टअप्स और डिजिटल नवोन्मेषियों के बीच निवेशकों के भरोसे को बढ़ाने में मदद करते हैं। डिजिटल डिलीवरी सेवाओं के अलावा, एफटीए ने भारत को वार्ताओं में नए तरीके अपनाने का मौका दिया है, जिससे ऐसी बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं हासिल हुई हैं, जो भारतीय प्रतिभा, खासकर युवाओं के आवागमन को बढ़ाती हैं। मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं – छात्र और पेशेवरों के लिए आवागमन प्रावधान और साइड–लेटर, भारत–यूके दोहरा योगदान समझौता (डीसीसी) जैसे फ्रेमवर्क, जो अस्थायी कार्य के लिए दोहरी सामाजिक सुरक्षा कराधान को रोकते हैं, और योग जैसे खास क्षेत्रों में आवागमन अधिकार। भारत के नई पीढ़ी के एफटीए की एक विशेषता व्यापार और निवेश के बीच गहरे संबंध को मान्यता देना है। प्रमुख वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करके और प्रमुख निर्माण सामग्री के आयात को आसान बनाकर, यह नेटवर्क बढ़ती मांग के साथ मिलकर भारत को निर्माण और निवेश के लिए बेहद आकर्षक गंतव्य बनाता है। हाल के समझौते और आगे बढ़ते हुए बाजार तक पहुंच को निवेश परिणामों से सीधे जोड़ते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण है, भारत–ईएफटीए समझौता, जिसमें यह शर्त रखी गयी है कि ईएफटीए देशों को भारतीय बाजार तक पहुंच तभी मिलेगी, जब वे 100 बिलियन डॉलर के एफडीआई का वादा करेंगे और भारत में दस लाख नौकरियाँ पैदा करेंगे। भारत–न्यूजीलैंड एफटीए में भी ऐसे ही प्रावधान हैं, जिनके तहत लंबे समय के निवेश के वादे के बदले भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार तक पहुंच की सुविधा दी गयी है। आधुनिक व्यापार अब केवल टैरिफ तक सीमित नहीं है इसके लिए 21वीं सदी के आयामों को समझना और नियमों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी), स्वच्छता और पादप–स्वच्छता से जुड़े उपाय (एसपीएस), और व्यापार सुगमता (टीएफ)। भारत के अगली पीढ़ी के एफटीए इन रूपरेखाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अक्सर, टैरिफ की तुलना में उत्पाद मानक और अन्य नियामक आवश्यकताएं बाजार तक पहुँचने में ज्यादा बड़ी रुकावटें पैदा करती हैं। भारत के एफटीए में नियामक समन्वय और सहयोग के प्रावधान भारतीय निर्यातकों के संदर्भ में इन बाधाओं को कम करने के लिए व्यवस्थित व संस्थागत तरीके प्रदान करते हैं। पर्यावरण और श्रम मानक व्यापार में संभावित बाधाओं के रूप में उभर रहे हैं और इनके लिए उपाय न करना अब कोई विकल्प नहीं है। भारत के नए एफटीए इन चिंताओं को दूर करने के लिए ऐसी सहयोगात्मक व्यवस्था पेश करते हैं, जिससे भारतीय हितों को नुकसान न पहुंचे। ये वैश्विक साझेदारों को भरोसा दिलाते हैं कि भारत मानकों के मामले में सबसे निचले स्तर पर पहुँचने की होड़ से बचते हुए, वास्तविक नवाचार और बड़े पैमाने पर काम करके प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करना चाहता है। भारत की एफटीए नीति टुकड़ों में नहीं है, या देश–दर–देश नहीं है। यह जानबूझकर ऐसी पूरक अर्थव्यवस्थाओं को लक्षित करती है, जिनकी वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में दो–तिहाई और वैश्विक आयात मांग में 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन एफटीए पर बातचीत हितधारकों की निरंतर भागीदारी और संपूर्ण सरकार दृष्टि पर निर्भर करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि व्यापार नीति भारत के औद्योगिक विकास, नवाचार और सामाजिक–आर्थिक प्रगति जैसी व्यापक प्राथमिकताओं के अनुरूप है और समझौते इस तरह से बनाए जाएँ कि संवेदनशील क्षेत्र और आबादी सुरक्षित रहें। खास तौर पर, एफटीए में ऐसे मजबूत प्रावधान शामिल किये जाते हैं, जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि भारतीय बाजार को खोलने से घरेलू हितधारकों को नुकसान नहीं होगा। संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्रों में उदारीकरण लंबे समय में धीरे–धीरे किया जाता है, ताकि स्थानीय उद्योगों को तालमेल बिठाने का समय मिल सके। कृषि जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों को एमएसएमई और किसानों की सुरक्षा के लिए बाहर रखा गया है।

संक्षिप्त खबरें

आठवें वेतन आयोग से बाहर रहेंगे शिक्षक और बिजली कर्मी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए आठवें वेतन आयोग के दल की ओर से बातचीत के लिए न बुलाए जाने पर राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और बिजली कर्मियों के संगठनों ने विरोध जताया है। प्रेस क्लब में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने इसे भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आयोग अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों से वार्ता कर रहा है, लेकिन राज्य कर्मचारियों को अवसर नहीं दे रहा। दुबे ने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों का वित्तीय भार राज्यों पर पड़ता है। इसलिए राज्य कर्मियों का पक्ष सुने बिना न्यायपूर्ण रिपोर्ट संभव नहीं। यूपी में पांचवें वेतन आयोग के बाद से राज्य कर्मियों का वेतन केंद्र के आयोगों की संस्तुतियों पर आधारित है। राज्य में वेतन पुनरीक्षण के लिए कोई अलग आयोग नहीं बना। आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों का सीधा असर लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा।

आभास ने साबित की श्रेष्ठता

लखनऊ, (संवाददाता)। कर्नल एसएन मिश्रा ओबीई मेमोरियल स्कूल में लखनऊ क्लासिकल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का खिताब आभास कुमार श्रीवास्तव ने अपने नाम किया। उन्होंने कुल 6.5 अंक अर्जित कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंतिम चक्र में आभास ने अभिनव कीर्ति के साथ अपनी बाजी ड्रॉ खेली। दूसरे स्थान के लिए अभिनव कीर्ति और पार्थ गुप्ता के बीच 6–6 अंकों पर बराबरी रही। टाई–ब्रेक के आधार पर अभिनव कीर्ति को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया। पार्थ गुप्ता को तृतीय स्थान पर संतोष करना पड़ा। पवन बाथम ने 5.5 अंक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। आकाश त्रिपाठी ने भी 5.5 अंक अर्जित कर पांचवां स्थान हासिल किया।टूर्नामेंट में विभिन्न आयु वर्गों एवं विशेष श्रेणियों में भी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वेटरन वर्ग में के. एम. शुक्ला विजेता बने। महिला वर्ग का खिताब संस्कृति यादव ने अपने नाम किया। अंडर–15 वर्ग में शुभ श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की। अंडर–13 वर्ग में कुनाल कुमार विजेता रहे। अक्षत श्रीवास्तव ने अंडर–11 वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। अंडर–9 वर्ग में अव्याना ने खिताब कब्जाया।

युवक की मौत पर किसान नेताओं ने किया प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। काकोरी के गोला कुआं गांव के पास शनिवार रात सड़क हादसे में हिमालय गौतम की मौत के अगले दिन रविवार को भी माहौल गरमाया रहा। पोस्टमार्टम हाउस से शव घर पहुंचने की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने परिजनों के साथ हाईवे जाम करने का प्रयास किया। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने आरोपी एसयूवी चालक की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। करीब आधे घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। मलिहाबाद एसडीएम अंकित मौर्य ने किसान नेताओं और परिजनों को समझाकर शांत कराया। किसान नेताओं ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने हरसंभव सहायता और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आईएमए लखनऊ में योग का संदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) लखनऊ शाखा द्वारा आईएमए भवन में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सकों एवं आईएमए सदस्यों ने भाग लेकर योग के महत्व को समझा और इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। आयोजन का उद्देश्य चिकित्सकों के बीच शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा समाज को योग के प्रति प्रेरित करना था।कार्यक्रम में प्रयाग आरोग्यम् केंद्र, योग प्रशिक्षण एवं योगाभ्यास केंद्र की योग गुरु ज्योति यादव ने प्रतिभागियों को लगभग एक घंटे तक विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान संबंधी अभ्यास कराए। उन्होंने बताया कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कहा कि नियमित योगाभ्यास से तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और जीवन अधिक संतुलित एवं ऊर्जावान बनता है।इस अवसर पर आईएमए लखनऊ की सचिव डॉ. श्वेता श्रीवास्तव ने कहा कि योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है, बल्कि इसे जीवनशैली का हिस्सा बनाना आवश्यक है। वर्तमान समय में बढ़ते कार्यभार और तनावपूर्ण जीवन के बीच चिकित्सकों के लिए योग और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

सीएचसी मलिहाबाद के पीछे तालाब में मिला वृद्ध का शव

लखनऊ, (संवाददाता)। मलिहाबाद थाना क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के पीछे स्थित एक तालाब में वृद्ध का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकलवाकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान 70 वर्षीय रामप्रसाद रैदास के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 20 जून 2026 को सीतलन टोला निवासी संजय पुत्र पंचम ने थाना मलिहाबाद को सूचना दी कि सीएचसी मलिहाबाद के पीछे स्थित तालाब में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान तालाब के पानी में लगभग 70 वर्षीय एक वृद्ध का शव दिखाई दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक एवं फील्ड यूनिट को भी घटनास्थल पर बुलाया गया ताकि आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया जा सके।पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और उसकी पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। कुछ समय बाद ग्राम सहिमाबाद निवासी रमेश पुत्र रामप्रसाद और वीरेन्द्र पुत्र रामप्रसाद मौके पर पहुंचे। दोनों ने शव की पहचान अपने पिता रामप्रसाद रैदास पुत्र स्वर्गीय लेखन रैदास, उम्र लगभग 70 वर्ष, के रूप में की।परिजनों ने पुलिस को बताया कि रामप्रसाद रैदास 19 जून को अपने ससुराल जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो सका।

महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना पुनीत कार्य : अनीता सिंह

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय संस्था अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयोजित 30 दिवसीय निःशुल्क सौंदर्य प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन समारोह सोमवार को टीप–टॉप ब्यूटी पार्लर, टीडी कॉलेज दक्षिणी गेट स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कोतवाली की पहली महिला कोतवाल अनीता सिंह एवं साइबर सेल की महिला थाना प्रभारी नीलम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। ट्रस्ट की अध्यक्ष उर्वशी सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक कार्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि अनीता सिंह ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना एक नेक और पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट द्वारा महिलाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाने की दिशा में किया जा रहा कार्य सराहनीय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन–प्रशासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी संस्था को दिलाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे ऐसे कार्यक्रमों का और विस्तार हो सके। उन्होंने मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों तथा हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी। विशिष्ट अतिथि नीलम सिंह ने भी महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया। समारोह में प्रशिक्षक सीमा गुप्ता एवं क्षमा सिंह के साथ अतिथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में प्रियंका मौर्य को बेस्ट मेकअप, तनुप्रिया सिंह को बेस्ट हेयर कट, वंदना सोनकर को हेयर डू तथा साहिबा अफसर को बेस्ट स्किन श्रेणी में सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में सुधा सिंह, रीना, आलिया, सुमन, मिनू और अनीता ने प्रशिक्षक के रूप में योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में महासचिव राधिका सिंह एवं नीलम मिश्रा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों व नीट के कई छात्रों की मौत पर एआईडीएसओ ने दिया श्रद्धांजलि

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। लखनऊ के अलीगंज में एक कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगने की वजह से 15 छात्रों व नीट के कई छात्रों की मौत पर ऑल इण्डिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को बदलापुर स्थित सब्जी मण्डी के पास श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें छात्र–छात्राओं व अभिभावकों ने मृत छात्रों के प्रति प्रतिकात्मक वेदी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। एआईडीएसओ के उत्तर प्रदेश राज्य सचिव दिलीप कुमार ने अलीगंज के कोचिंग सेंटर में हुए इस भीषण अग्निकांड व नीट के दिवंगत छात्रों के लिए गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुःखद व चिंताजनक है। उन्होंने मृत छात्रों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना से छात्रों व अभिभावकों में गहरा दुख व विक्षोभ व्याप्त है। इस दुःखद घटना से साफ जाहिर है कि शासन–प्रशासन की लापरवाही और कोचिंग संस्थानों की लूट से आये दिन छात्रों के साथ कोई न कोई अनहोनी हो रही है। दरअसल, सरकार व पूंजीपतियों की मंशा के अनुरूप सरकारी शिक्षण संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है और शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहित करते हुए सरकार सुरक्षा व उपयुक्त मानकों का ख्याल किए बगैर कोचिंग संस्थानों को लूट की छूट दे रही है। परिणामस्वरूप शिक्षा प्राप्त करने की जद्दोजहद में छात्रों को अपना जीवन तक गंवाना पड़ रहा है। इसलिए ऐसी दुःखद घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी स्कूल–कॉलेजों की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना चाहिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए और निजीकरण पर रोक लगाकर शिक्षा क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की स्थाई भर्ती करनी चाहिए। देश भर में मृतक छात्रों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए छात्र संगठन ।प्कै सरकार से मांग करता है कि, घायल छात्रों को तत्काल उचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाए। घटना के कारणों की उपयुक्त जांच हो। मृतक व घायल छात्रों नौजवानों को उचित मुआवजा दिया जाए। घटना के दोषियों को कठोर सजा दी जाए। छात्रों के जीवन को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त कदम उठाये जाएं। इस अवसर एआईडीएसओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सचिन जैन, प्रवीण विश्वकर्मा, अंजली सरोज, पूनम प्रजापति, विकास मौर्य, जयंत राव, विजयप्रकाश, वर्षा, अजय मौर्य, सहित अन्य कई छात्र छात्रायें मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन– संतोष कुमार प्रजापति ने किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नगर निगम मुख्यालय में भव्य योगाभ्यास

लखनऊ, (संवाददाता)। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर निगम लखनऊ मुख्यालय स्थित झंडी पार्क में भव्य सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों, कर्मचारियों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता करते हुए योग के माध्यम से स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर सुषमा खर्कवाल रहीं, जिन्होंने स्वयं योगाभ्यास में भाग लेते हुए सभी उपस्थित लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प दिलाया।कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के श्रवण के साथ हुई। झंडी पार्क में स्थापित बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से उपस्थित लोगों ने दोनों नेताओं का उद्बोधन सुना। अपने संदेश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने योग के महत्व, स्वस्थ जीवनशैली तथा राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इसके बाद आयुष विभाग के प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों ने सभी प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया।इस अवसर पर महापौर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है, जिसे आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज विश्व के अनेक देशों में लोग योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि यह मन, मस्तिष्क और आत्मा को भी संतुलित करने का प्रभावी साधन है। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योग एवं आयुष पद्धति को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की विभिन्न पहल के माध्यम से योग को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे निरोग और स्वस्थ समाज के निर्माण को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर जीवन की नियमित आदत बनाना चाहिए।'योग फॉर हेल्दी एजिंग' विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने योग के माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने पर बल दिया।

राम मंदिर चंदा और जमीन खरीद मामलों की जांच की मांग को लेकर आप का भिक्षाटन प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। भगवान श्रीराम मंदिर से जुड़े चंदा और जमीन खरीद मामलों में कथित अनियमितताओं के विरोध में आम आदमी पार्टी ने रविवार को प्रदेशव्यापी भिक्षाटन अभियान चलाया। पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों और प्रमुख चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई ।इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के स्वास्थ्य भवन चौराहे पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरे और तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ष्चंदा चोरों गद्दी छोड़ोष्, ष्राम भक्तों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तानष् और ष्श्रीराम के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करोष् जैसे नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से 420 रुपये का चेक तैयार कर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेजने की घोषणा की।प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पार्टी के ऑटो विंग प्रदेश अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह सलूजा ने आरोप लगाया कि भगवान श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए देश–विदेश के श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ दान दिया था,।

डेनमार्क में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे डॉ नितेश जायसवाल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) भौतिक विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग में कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. नितेश जायसवाल को डेनमार्क के ओडेंस में 28 जून से 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होने वाले 46वें अंतरराष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सम्मेलन में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्षेत्र का विश्वस्तरीय एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन है, जो प्रत्येक दो वर्ष पर आयोजित होता है। इसमें विभिन्न देशों के अग्रणी वैज्ञानिक, शिक्षाविद एवं शोधकर्ता भाग लेते हैं। डॉ. जायसवाल इस सम्मेलन में अपने शोध विषय मल्टीफंक्शनल सिफ बेस मेटल कॉम्प्लेक्सेस पर मौखिक प्रस्तुति देंगे। उनका शोध कार्य संक्रमण धातु–आधारित उपसहसंयोजक यौगिकों के संश्लेषण, संरचनात्मक अध्ययन तथा उनके जैविक एवं औद्योगिक अनुप्रयोगों से संबंधित है। डॉ. जायसवाल को इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागिता हेतु अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, भारत सरकार की अंतरराष्ट्रीय यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा अनुदान स्वीकृत हुआ है। इस अनुदान के माध्यम से उन्हें अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, वीजा शुल्क तथा सम्मेलन पंजीकरण शुल्क आदि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपसहसंयोजक यौगिकों के जैविक एवं चिकित्सीय अनुप्रयोग, उत्प्रेरण, ऊर्जा एवं स्थिरता के लिए समन्वय यौगिक, आणविक मॉडलिंग तथा उन्नत पदार्थ विज्ञान जैसे समसामयिक विषयों पर व्याख्यान एवं प्रस्तुतियां होंगी। डॉ. जायसवाल की इस उपलब्धि पर मंगलवार को कुलपति प्रो वंदना सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। संस्थान के निदेशक प्रो मिथिलेश सिंह, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रो. प्रमोद कुमार यादव ने डॉ नितेश जायसवाल को बधाई व शुभकामनाएं दी। रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. प्रमोद कुमार ने कहा कि डॉ जायसवाल की सहभागिता विश्वविद्यालय की अंतरराष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करेगी तथा वैश्विक शोध सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम ने एनसीसी सीएटीसी कैंप का किया निरीक्षण, कैडेटों को किया प्रेरित

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय परिसर में 98 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (सीएटीसी)–318 में मंगलवार को उत्तर प्रदेश एनसीसी मुख्यालय, लखनऊ के एडीजी मेजर जनरल गौरव गौतम का आगमन हुआ। उनके पहुंचने पर एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी के ग्रुप कमांडर विकास पंजियार, कैंप कमांडेंट कर्नल आलोक डी. सिंह तथा एनसीसी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मेजर जनरल गौरव गौतम ने शिविर का निरीक्षण कर कैडेटों को दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ली। उन्होंने ड्रिल, मैप रीडिंग, फील्ड एवं बैटल क्राफ्ट, फायरिंग तथा व्यक्तित्व विकास से संबंधित गतिविधियों का अवलोकन किया। प्रशिक्षण प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना एनसीसी की सबसे बड़ी पहचान है। अपने संबोधन में उन्होंने कैडेटों को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और निर्णय लेने की योग्यता विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कैडेट को किसी न किसी रचनात्मक शौक को अपनाना चाहिए, आत्मरक्षा में दक्षता हासिल करनी चाहिए तथा अपनी प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें निखारने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दूसरी भाषा सीखने, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन में एक आदर्श रोल मॉडल का अनुसरण करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनाने के साथ–साथ उनमें राष्ट्रभक्ति, आत्मविश्वास और सेवा भावना का विकास करती है। उन्होंने कैडेटों से प्रशिक्षण के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाने और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। मेजर जनरल गौतम ने शिविर की व्यवस्थाओं एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों और प्रशिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने 98 यूपी बटालियन की प्रशिक्षण टीम को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए विशेष रूप से बधाई दी। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई आवासीय एवं प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए कुलपति प्रो. वंदना सिंह तथा विश्वविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में एनसीसी अधिकारी, एएनओ तथा बड़ी संख्या में कैडेट उपस्थित रहे। मेजर जनरल गौरव गौतम के मार्गदर्शन से कैडेटों में उत्साह, आत्मविश्वास और राष्ट्रसेवा के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ।

निर्विरोध चुने गए नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो गया । सुबह 11रू00 बजे शुरू हुई नगर निगम सदन की विशेष बैठक में भाजपा की ओर से पांच और सपा की ओर से एक प्रत्याशी ने नामांकन किया । नामांकन पत्रों की जांच के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल ने सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया है । चुनाव निर्विरोध होगा इसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी । दोनों दलों ने मिलकर उतने ही प्रत्याशी उतारे जितने पद खाली थे। अब नगर निगम की 12 सदस्यीय कार्यकारिणी में भाजपा के 10 और सपा के दो पार्षद हो जाएंगे । पहले भी यही स्थिति थी। छह पदों पर यह चुनाव बीती एक जून को दो साल का कार्यकाल पूरा कर रिटायर हुए छह सदस्यों की जगह पर किया गया है। सपा की ओर से पहले जगदीश चंद्र बोस वार्ड से लगातार छह बार जीत दर्ज करने वाले पार्षद यावर हुसैन रेशू को प्रत्याशी बनाए जाने की संभावना देर रात तक थी लेकिन सुबह सदन में अचानक पहली बार भरवारा मल्हौर वार्ड से पार्षद बनी ममता रावत को टिकट दे दिया गया। टिकट देने की जानकारी भी महापौर को ममता रावत ने दल के नेता कामरान बेग से फोन पर बात कराकर दी। चुनाव के दौरान सपा पार्षद दल के नेता कामरान बेग सदन में मौजूद नहीं रहे। इससे पार्षद यावर हुसैन रेशू खासे नाराज दिखे।

भाषा विवि में 139 रिक्त सीटों पर प्रवेश का अवसर

लखनऊ, (संवाददाता)। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और विधि पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए सूचना जारी की है। अभ्यर्थियों को संशोधित प्रतीक्षा सूची और कॉमन सूची के आधार पर यह अवसर मिलेगा। कुल 139 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। विवि के प्रवेश समन्वयक सौवान सईद ने बताया कि बीकॉम., बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी), बीए एलएलबी. और एलएलबी. पाठ्यक्रमों में ये सीटें उपलब्ध हैं। बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी) और बीकॉम की संशोधित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को 23 जून को रिपोर्ट करना होगा। बीए एलएलबी और एलएलबी की 19 जून को प्रकाशित कॉमन सूची के अभ्यर्थियों को भी इसी दिन दोपहर एक बजे तक कक्ष संख्या 245 में उपस्थित होना है। काउंसिलिंग के तुरंत बाद प्रवेश शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। बीकॉम में सामान्य वर्ग की छह, अन्य पिछड़ा वर्ग की नौ, अनुसूचित जातिध्जनजाति की चार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पांच सीटें रिक्त हैं। बीएससी (बायोटेक्नोलॉजी) में सामान्य वर्ग की 22, ओबीसी की 15, एससीध्एसटी की 10 और ईडब्ल्यूएस की पांच सीटें उपलब्ध हैं। बीए एलएलबी में सामान्य वर्ग की 15, ओबीसी की सात, एससीध्एसटी की चार और ईडब्ल्यूएस की पांच सीटें खाली हैं। एलएलबी में सामान्य वर्ग की 11, ओबीसी की आठ, एससीध्एसटी की सात और ईडब्ल्यूएस की छह सीटें हैं।

लखनऊ में हुये भीषण अग्निकांड में मृतकों को रेडक्रॉस ने दी श्रद्धांजलि’

’ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

’शाहजहांपुर’ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी,जनपद शाखा की एक आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ के एक आवासीय क्षेत्र स्थित तीन मंजिला आवासीय–व्यावसायिक भवन में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 15 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतकों की आयु लगभग 18 से 22 वर्ष के बीच थी तथा अधिकांश मौतें दम घुटने के कारण हुईं।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की तथा शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस दुःखद हृदयविदारक घटना के उपरांत राहत एवं सहायता कार्यों में तत्परता दिखाते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और तुरंत राहत कार्य प्रारंभ कराए गए। रेडक्रॉस की जनपद स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उपमुख्यमंत्री सह सभापति इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी उत्तर प्रदेश के मानवीय प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ. विजय जौहरी ने कहा कि ऐसी घटनाएँ फर्स्ट एड एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, सरकारी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं तथा सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कर्मियों को प्राथमिक उपचार एवं आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाना समय की आवश्यकता है। डॉ. जौहरी ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वर्षों से फर्स्ट एड एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन, अग्निशमन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संस्थानों से अनुरोध किया कि अधिकाधिक लोगों को रेडक्रॉस के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाए, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में जनहानि को कम किया जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जिलाधिकारी एवं रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सहित संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाने का अनुरोध किया जाएगा। अंत में रेडक्रॉस सोसाइटी ने पुनः दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा संकट की इस घड़ी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रदेश सभापति एवं उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में खड़ी है इस बैठक में ॐ दिव्यांगजन कल्याण समिति के बालकृष्ण पाण्डेय, मीनू मिश्रा,बृजेश गुप्ता, राखी बनकोटी, अनुज जौहरी, अग्रज जौहरी अवनीश सक्सेना, आदि मौजूद रहे। अंत में रेडक्रॉस सचिव डॉ विजय जौहरी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए मानव सेवा में सभी से सहयोगी भूमिका की अपेक्षा की।

शिक्षकों की समस्याओं एवं शिक्षा की गुणवत्ता पर हुई व्यापक चर्चा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन शैक्षिक संगोष्ठी एवं वित्तविहीन शिक्षकों की समस्याओं के समाधानार्थ वेतन निर्धारण कार्यशाला का आयोजन सोमवार को विश्वहरैया सभागार में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीता चौधरी ने की। कार्यशाला के मुख्य अतिथि माननीय लाल बिहारी यादव, सदस्य, वित्तविहीन वेतन परिषद एवं नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा वित्तविहीन शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से शिक्षकों के मानदेय, सेवा सुरक्षा, पुरानी पेंशन योजना तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। अपने संबोधन में श्री लाल बिहारी यादव ने कहा कि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के आगामी चुनाव शिक्षकों के अधिकारों और सम्मान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने शिक्षकों से अधिकाधिक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया ताकि शिक्षक समाज की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन में उठाया जा सके। उन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय, सेवा नियमावली के संरक्षण तथा चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था हेतु निरंतर प्रयासरत रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की सेवाओं को सुरक्षित बनाए जाने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन निरंतर संघर्ष कर रहा है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व में किए गए कार्यों एवं शिक्षकों को प्रदान की गई सुविधाओं का भी उल्लेख किया। संगोष्ठी को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल, सांसद फतेहपुर सहित विभिन्न शिक्षक विधायक प्रत्याशियों एवं संगठन के पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम यादव, रामबरन यादव, मुमताज अली सहित प्रदेश एवं जनपद स्तर के अनेक पदाधिकारी, शिक्षक प्रतिनिधि एवं शिक्षाविद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षता कर रहीं श्रीमती रीता चौधरी ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं शिक्षकों का आभार व्यक्त किया तथा सभा के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

पूर्व सांसद लल्लू सिंह द्वारा लता चौक पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। जेठ के आखिरी मंगलवार पर अयोध्या का लता चौक भक्ति, सेवा और श्रद्धा के अनुपम संगम का साक्षी बना।पूर्व सांसद लल्लू सिंह की संस्था श्री अयोध्या न्यास द्वारा आयोजित विशाल भंडारे का शुभारंभ मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने किया। इस दौरान हनुमत सदन के महंत अवध किशोर शरण, हनुमानगढ़ी के सरपंच महंत रामकुमार दास, बड़ा भक्तमाल महंत अवधेश दास, महंत सीताराम दास, महंत निर्मल शरण, पुजारी प्रकाश दास मौजूद थे।पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने संतों रामनामा देकर अभिवादन किया। आयोजन स्थल पर गूंजते राम भजनों ने वातावरण को भक्तिरस से सराबोर कर दिया। श्रद्धालुओं की निरंतर उमड़ती भीड़ के बीच सेवा का भाव हर ओर दिखाई दे रहा था।भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशाल पंडाल की व्यवस्था की गई। यातायात तथा अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए वालंटियर की तैनाती की गई थी। वहीं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते रहे।भंडारे में महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, मंडलायुक्त राजेश कुमार, डॉ बांके बिहारी मणि त्रिपाठी, अवधेश पांडे बादल, संजीव सिंह, अभिषेक मिश्रा, कमला शंकर पांडे, कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू, करुणाकर पांडे, विश्वनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष विजय गुप्ता, मनोज जायसवाल, शैलेंद्र कोरी, तिलक राम मौर्य, डिप्टी मेयर संतोष सिंह, सुनील शास्त्री, गिरीश पांडे डिप्पुल, कप्तान सिंह, मनमोहन जायसवाल, देवता पटेल, विपिन सिंह बब्लू, चंद्रभान सिंह, अनूप सिंह रानू, बबलू पासी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी,कार्यकर्ता ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया।

महिला उप निरीक्षक चेतना पाण्डेय ने महिलाओ को किया जागरूक

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।मंगलवार को मिशन शक्ति अभियान फेज–5 के तहत गोशाईगंज थाना पर तैनात महिला उप निरीक्षक चेतना पाण्डेय ने महिला आरक्षी संजू दूबे व दीक्षा के साथ गोशाईगंज के प्रमुख बैंको सहित अन्य प्रमुख चौराहों तथा मार्गों पर महिलाओ को उनके सुरक्षा के प्रति जागरुक किया।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बेटियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक व सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी दिया।उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और

हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकती है।

’कलेक्ट्रेट में अभिलेखागार विस्तार एवं नवीन सभागार निर्माण को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण’

’ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

’शाहजहाँपुर’ मंगलवार को डीएम धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रजनीश कुमार मिश्र एवं नगर मजिस्ट्रेट रजनीकांत के साथ कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम) के विस्तारीकरण कार्य तथा निर्वाचन कार्यालय को बिस्मिल सभागार में स्थानांतरित किए जाने एवं वर्तमान निर्वाचन कार्यालय के स्थान पर नवीन एवं बड़े सभागार के निर्माण की संभावनाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट स्थित अभिलेखागार के विस्तारीकरण कार्य की प्रगति का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि अभिलेखागार की सुरक्षा एवं अभिलेखों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भवन में किसी प्रकार की अनावश्यक खिड़की, वेंटिलेशन अथवा एग्जॉस्ट की व्यवस्था न रखी जाए। साथ ही उन्होंने कार्य पूर्ण होने के उपरांत भवन की गुणवत्तापूर्ण रंगाई पुताई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी ने बिस्मिल सभागार परिसर का निरीक्षण कर वहां निर्वाचन कार्यालय को स्थानांतरित किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही वर्तमान निर्वाचन कार्यालय के स्थान पर एक आधुनिक एवं अधिक क्षमता वाले नवीन सभागार के निर्माण के संबंध में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सभागार में बैठकों एवं विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान अधिक संख्या में लोगों के उपस्थित होने पर स्थान की कमी के कारण असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रस्तावित सभागार के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण एवं मापन कराते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं आगणन तैयार किया जाए, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशाल एवं सुविधायुक्त सभागार का निर्माण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए पर्याप्त क्षमता वाला सभागार की आवश्यकता है, जिसके दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाए।

ग्रामीण युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए डी.डी.यू.–जी.के.वाई.ओरिएंटेशन कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन

अयोध्या।अयोध्या मंडल के अम्बेडकर नगर जिले मे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत मॉडर्न बेबी नर्सरी स्कूल समिति द्वारा अम्बेडकर नगर में एक भव्य ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रशिक्षु अपने अभिभावकों के साथ उपस्थित हुए, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और ऊर्जा का वातावरण दिखाई दिया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला परियोजना समन्वयक, DDU-GKY नीरज सिंह रहे।उन्होंने युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि DDU-GKY ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रभावी पहल है।इस अवसर पर परियोजना प्रमुख सत्यदेव श्रीवास्तव ने प्रशिक्षुओं एवं उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रशिक्षण, छात्रावास, भोजन, यूनिफॉर्म, अध्ययन सामग्री, रोजगार के अवसरों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षण अवधि का पूर्ण लाभ उठाकर अपने जीवन एवं करियर को नई दिशा देने का आह्वान किया।कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया तथा उन्हें प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।इस अवसर पर सेंटर मैनेजर अभिषेक, क्वालिटी हेड वर्षा श्रीवास्तव, आशा गौड़,विपिन,राज तथा कृषि सखी राधा सहित संस्था के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।इस मौके पर सभी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अभिभावकों एवं युवाओं ने DDU-GKY योजना के प्रति उत्साह व्यक्त करते हुए इसे ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रभावी कदम उठाने में सरकार विफल - प्रियंका गुप्ता

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। नीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन की विफलताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पत्रकार वार्ता की।प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2015 से लेकर हाल के वर्षों तक कई बार नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद केंद्र सरकार और संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रभावी सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए।कांग्रेस पार्टी लगातार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्रों के हितों की रक्षा की मांग करती रही है।कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों के बीच गहरी चिंता व्याप्त है। परीक्षा प्रणाली में खामियों के कारण छात्रों को मानसिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की बड़ी आर्थिक भागीदारी होती है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य पर प्रहार है।प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया "छात्रों की गूंज" अभियान देशभर के छात्रों की आवाज को सुनने, उनकी समस्याओं को समझने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सुझाव एकत्रित करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो युवाओं को अवसर प्रदान करे, उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न डाले और उन्हें सुरक्षित एवं निष्पक्ष प्रतियोगी वातावरण उपलब्ध कराए। जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते निजीकरण, सरकारी विद्यालयों की उपेक्षा, शिक्षकों के रिक्त पद तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय हैं।महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छात्रों, युवाओं और अभिभावकों के साथ खड़ी है तथा निष्पक्ष, पारदर्शी और सुलभ शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। उन्होंने प्रदेश के छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि वे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने की इस मुहिम में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं।जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने कहा पिछले 12वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं लेकिन सरकार ने किसी भी परीक्षा लीक की एफ आई आर नहीं लिखाई इसी से सरकार की संलिप्तता दर्शाती है।प्रमुख रूप से पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप, सिंह ,पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, जिला अध्यक्ष रेनू राय,पीसीसी सदस्य उग्रसेन मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह फास्टर ,मोहम्मद आमिर, अशोक राय उपस्थित रहे।

करेंट की चपेट में आई किशोरी,जिला अस्पताल से रेफर

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। रौनाही थाना क्षेत्र में सोमवार को एक किशोरी करेंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जिला अस्पताल लाए जाने पर हालत गंभीर देख उसको हायर सेंटर रेफर किया गया है।बताया गया कि थाना क्षेत्र के मजनावां गांव निवासी 15 वर्षीय सावित्री पुत्री कन्हैयालाल दूसरे पहर अपने खेत गई थी। इसी दौरान वह पड़ोसी किसान की ओर से जानवरों की सुरक्षा के लिए अपने खेत में फैलाए गए विद्युत तार के संपर्क में आ गई । मामले की जानकारी पर किशोरी के भाई शिवम ने शाम को उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर विशाल चौधरी में प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख किशोरी को मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर कर दिया।

राजधानी के कोचिंग मे भीषण अग्निकांड के बाद एक बार फिर जागा शिक्षा व फायर विभाग

अयोध्या।सोमवार को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में में हुई भीषण अधिकांड में एक दर्जनों छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद अयोध्या में भी शिक्षा व फायर विभाग के अधिकारी व कर्मी जाग गए है।मंगलवार को इन दोनों विभागों के अधिकारी तथा कर्मियों ने ताबडतोड कार्यवाही करते हुए कई होटल,पेइंग गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट कोचिंग सेंटर,लाइब्रेरी सहित अन्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का औचक निरीक्षण किया। सवाल यह उठता है कि आए दिन जब कोई बड़ी घटना होती है तब इस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है तो इनका ध्यान अयोध्या के गली मोहल्ले में कोचिंग,लाइब्रेरी होटल, गेस्ट हाउस और नर्सिंग होम पर क्यों नहीं पड़ता है।जिसमें कईयों को फायर विभाग की एनओसी भी नहीं है, चूंकि अगर कोई घटना हुई तो ऐसे में स्थानों पर न तो फायर का वाहन जा की सकता है न ही एंबुलेंस जा सकती है।देखा जाये तो शहर के गली गली मे कोचिंग,लाइब्रेरी,होटल व रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस खुल चुके है।गेस्ट हाउस तथा रेस्टॉरेंट होटल मानक पर खरे नहीं उतर रहे है बीच–बीच में जब कोई आसपास के जिलों मे कोई घटना घटती है तो संबंधित विभाग कुंभकर्णी नींद से जागता है और जांच पडताल शुरू करता है उसके बाद मामला ठंडा बस्ते में चला जाता है। डीआईओएस डॉक्टर पवन कुमार तिवारी तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि शहर में देखा जाए तो कल तीन दर्जन ही कोचिंग संस्थान जिसमें लाइब्रेरी ही मानक पर खड़े उतर रहे हैं।इन दोनों अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन तथा शिक्षा विभाग द्वारा टीम गठित कर अवैध रूप से संचालित कोचिंग लाइब्रेरी होटल रेस्टोरेंट सहित अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन कार्यवाही कितनी हुई इसका जवाब इन दोनों अधिकारियों पर नहीं है सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि नोटिस जारी की गई है।

‘जिलाधिकारी ने जन सुनवाई में सुनी 59 शिकायतें’

’ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव’

’हरदोई’ मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में कुल 59 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण

समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट डॉ अरूणिमा श्रीवास्तव व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीध कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ कोचिंग हादसे मे छात्रों के आसामयिक मौत मे राजकीय जिला पुस्तकालय शोक सभा का हुआ आयोजन

अयोध्या।लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में 15 छात्र–छात्राओं के असामयिक निधन पर मंगलवार को राजकीय जिला पुस्तकालय जनपद अयोध्या पर शोक सभा का आयोजन किया गया।जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पुस्तकालय परिसर में जिला मंत्री आलोक तिवारी ने सभी सदस्य दिवंगत छात्र–छात्राओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया।तथा शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया।श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिवारों को यह वज्रपात सहने की शक्ति प्रदान करें।कार्यक्रम में जिला मंत्री आलोक तिवारी, शक्ति सदस्य विनोद कुमार मिश्रा,सुषमा मिश्रा, अनूप पांडे,सत्य प्रकाश सत्य, उपस्थित रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।